



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 1996/पाँच 22, 1917

No. 23]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 12, 1996/PAUSA 22, 1917

खाद्य मंत्रालय  
(खाद्य विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1996

सा. का. नि. 27(अ):—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 1995 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ग ग) “प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और निर्धारण परिषद् (टी. आई. एफ. एं. सी.) से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निकाय अभिप्रेत है”।

3. उक्त नियमों के नियम 16 में,

- (1) उपनियम (1) में, “उसकी सुसंगत स्कीम के अधीन” शब्दों के पश्चात् “अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का चीनी उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर मिशन मोड परियोजना” स्कीम की बाबत प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और निर्धारण परिषद् द्वारा प्रायागत, शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा;

- (2) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(6) (क) केन्द्रीय सरकार, समिति की सिफारिश पर और किसी अन्य सुसंगत बात पर विचार करने के पश्चात् उधार की ऐसी रकम का जो वित्तीय संस्था द्वारा ऐसे चीनी उपक्रम द्वारा संप्रवर्तक के अभिदाय के रूप में अभिदाय किए

जाने के लिए अपेक्षित रकम से अधिक नहीं है जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, किसी चीनी उपक्रम की संदाय किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी।

(ख) केन्द्रीय सरकार, प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और निर्धारण परिषद, (टी. आई. एफ. ए. सी.) द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के लिए समिति की सिफारिश पर और किसी अन्य सुसंगत बात पर विचार करने के पश्चात् किसी चीनी उपक्रम को ऋण की उस धनराशि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित, प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टी. आई. एफ. ए. सी.) द्वारा संस्तुत धनराशि से अधिक न हो, के भुगतान को प्राधिकृत कर सकेगी।

परन्तु निधि में ऋण की धनराशि परियोजना की पात्र लागत के माठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार खंड (क) और खंड (ख) के अधीन उक्त ऋण का भुगतान केवल ऐसे चीनी उपक्रमों को प्राधिकृत करेगी जिन्होंने चीनी विकास निधि और लेवी चीनी मूल्य समीकरण निधि की बाबत सभी धनराशियों का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया हो”;

परन्तु यह और कि खंड (ख) के अधीन स्वीकृत किए जाने वाले ऋण की स्कीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के “चीनी उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर मिशन मोड़ परियोजना स्कीम” के कार्यकाल के साथ कोटमिनस आधार पर होगी; परन्तु यह भी कि निधि से ऋण केवल तभी दिया जाएगा जब चीनी उपक्रम संप्रवर्तक के अभिदाय के रूप में अपने संसाधनों में, मांगे गए ऋण का न्यूनतम दस प्रतिशत का अभिदाय करता है परन्तु यह तब जब कि प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और निर्धारण परिषद (टी. आई. एफ. ए. सी.) द्वारा प्रायोजित परियोजना का वित्तीय मूल्यांकन लिया गया हो; यह मूल्यांकन वित्तीय संस्था द्वारा किया जाएगा जिसके लिए अपेक्षित सेवा प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वहन किए जाएंगे। प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और निर्धारण परिषद (टी. आई. एफ. ए. सी.) के अधीन आने वाले चीनी उपक्रम की परियोजना संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण के प्रयोजन के लिए होगी और ऐसे चीनी उपक्रम को विस्तार परियोजना के लिए लागू किसी प्रोत्साहन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार खंड (क) और खंड (ख) के अधीन उक्त ऋण का भुगतान केवल ऐसे चीनी उपक्रमों को प्राधिकृत करेगी जिन्होंने चीनी विकास निधि और लेवी चीनी मूल्य समीकरण निधि की बाबत सभी धनराशियों का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया हो ;

(3) (i) उप नियम (9) के खंड (iii) में, शब्द “प्रति वर्ष” के बाद;

“वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में और प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और निर्धारण परिषद द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के लिए छः प्रतिशत प्रति वर्ष” जोड़े जाएंगे।

(ii) खंड (iv) में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और निर्धारण परिषद द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के लिए इस निगम के अधीन ऋण पर व्याज सहित ऋण की वापसी ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् शुरू होगी जो वित्तीय संस्था द्वारा उचित रूप से गत्यापन करने के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी परन्तु इसकी अवधि अधिक से अधिक 5 वर्ष होगी, जिसकी गणना निधि से ऋण के संचित करने की तारीख से की जाएगी और निधि से ऋण और उस पर देय व्याज वार्षिक किस्तों जिनकी संख्या पांच से अधिक नहीं होगी, में वसूल किया जाएगा।

4. प्ररूप 2 में, मद VIII, मद IX, मद X और मद XI में शब्द संख्याओं शब्द के पश्चात् “प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और निर्धारण परिषद (टी. आई. एफ. ए. सी.) शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

[फाइल संख्या 1-2/94—एस. डी. एफ.]

नवीन कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण:—प्रधान नियम भारत के राजपत्र में तारीख 27 सितम्बर, 1983 को संख्या सा. का. नि. 752(ई) द्वारा प्रकाशित किया गया था; और बाद में निम्नलिखित संख्याओं द्वारा उसमें संशोधन किया गया था:—

- (1) सा. का. नि. 817(ई) तारीख 20 विसम्बर, 1984
- (2) सा. का. नि. 838(ई) तारीख 11 नवम्बर, 1985
- (3) सा. का. नि. 551(ई) तारीख 6 मई, 1988
- (4) सा. का. नि. 235(ई) तारीख 24 अप्रैल, 1991
- (5) सा. का. नि. 441(ई) तारीख 28 अप्रैल, 1992
- (6) सा. का. नि. 435(ई) तारीख 6 मई, 1994

## MINISTRY OF FOOD

(Department of Food)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 1996

G.S.R. 27(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules 1983, namely :—

1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Amendment) Rules 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Sugar Development Fund Rules, 1983 (hereinafter referred to as the said rules), after clause (c), the following shall be inserted, namely :—

“(oo) ‘Technology Information, Forecasting and Assessment Council’ (TIFAC) means a body registered under the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860).”

3. In rule 16 of the said rules.—

(1) in sub-rule (1) after the words “its relevant Scheme”, the words “or sponsored by the Technology Information Forecasting and Assessment Council, in respect of the scheme ‘Mission Mode Project on Sugar Production Technologies’ of the Department of Science and Technology” shall be inserted;

(2) for sub-rule (6), the following shall be substituted, namely :—

“(6)(a) The Central Government may, after consideration of the recommendation of the Committee and any other relevant factor, authorise payment to a sugar undertaking of such amount of loan, not exceeding the amount required by the financial institution to be contributed by such sugar undertaking as promoter's contribution, as may be determined by the Central Government.

(b) For the projects sponsored by Technology Information, Forecasting and Assessment Council, (TIFAC) the Central Government may, after consideration of the recommendation of the Committee and other relevant factors, authorise payment to a sugar undertaking of such amount of loan not exceeding the amount recommended by the Technology Information, Forecasting and Assessment Council (TIFAC) may be determined by the Central Government :

Provided that the amount of loan from the Fund shall not exceed sixty per cent of the eligible project cost :

Provided further that the scheme of loan to be sanctioned under clause (b) shall be coterminous with the duration of ‘Mission Mode Project Scheme on Sugar Production Technologies’ of Department of Science and Technology :

Provided also that the loan from the fund shall be granted only if the sugar undertaking contributes a minimum of ten per cent, of the loan applied for, from its own resources as promoter's contribution subject to the financial appraisal of the project sponsored by the Technology Information, Forecasting and Assessment Council, (TIFAC) which shall be undertaken by financial institution, for which the requisite service charges shall be borne by the Ministry of Science and Technology. The project of the sugar undertaking covered under Technology Information, Forecasting and Assessment Council, (TIFAC) shall be for the purpose of modernisation of plant and machinery and such sugar undertaking shall not be allowed any incentives applicable for expansion project :

Provided further that the Central Government shall authorise payment of the said loan under clauses (a) and (b) only to such sugar undertakings which have fully repaid all the sums due in respect of Sugar Development Fund and Levy Sugar Price Equalisation Fund ;”

3. (i) in clause (iii), of sub-rule (9),—after the words “per annum” the words :

“in respect of the projects approved by a financial institution and for the projects sponsored by the Technology Information, Forecasting and Assessment Council six per cent per annum” ; shall be inserted.

(ii) in clause (iv), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that for the projects sponsored by Technology Information, Forecasting and Assessment Council, the repayment of loan under this rule, together with interest thereon, shall commence after the expiry of such period as may be decided by the Central Government after due verification by Financial Institution subject to a maximum of 5 years, reckoned from the date of disbursement of the fund loan and the loan from the fund alongwith the interest due thereon, shall be recoverable in annual instalments not exceeding five in number”.

4. In Form-II, items VIII, IX, X and XI after the word ‘Institutions’, the words “Technology Information, Forecasting and Assessment Council (TIFAC)” shall be inserted.

[F. No. 1-2/94-SDF]

NAVIN KUMAR, Jt. Secy.

Foot Note.—The Principal rules were published in the Gazette of India No. GSR 752(E), dated 27th September, 1983 and subsequently amended vide number :—

- (i) GSR 817(E), dated the 20th December, 1984.
- (ii) GSR 838(E), dated the 11th November, 1985.
- (iii) GSR 551(E), dated the 6th May, 1988.
- (iv) GSR 235(E), dated the 24th April, 1991.
- (v) GSR 441(E), dated the 28th April, 1992.
- (vi) GSR 435(E), dated the 6th May, 1994.

